

## भारतीय अर्थव्यवस्था और इम्पॉसबिल ट्रनिटी

### प्रलिस के लयः

इम्पॉसबिल ट्रनिटी, [भारतीय रज़रव बैंक](#), [मौद्रकः नीतः](#), [वदःशी मुद्रा भंडार](#)

### मेन्स के लयः

इम्पॉसबिल ट्रनिटी को संभव बनाने में चुनौतयः, भारत की मुद्रा गतशीलता

[स्रोतः बज़नेस लाइन](#)

### चर्चा में क्यः?

वर्तमान में [भारतीय रज़रव बैंक \(RBI\)](#) और भारतीय नवःशकों को "इम्पॉसबिल ट्रनिटी" पर काबू पाने में एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है ।

### इम्पॉसबिल ट्रनिटी:

#### परचयः

- इम्पॉसबिल ट्रनिटी, या त्रलिसमा, इस वचःार को संदरभतः करता है कः एक अर्थव्यवस्थास्वतंत्र [मौद्रकः नीतः](#) नश्चितः वनःमिय दर नहीं बनाए रख सकती है और एक ही समय में अपनी सीमाओं के वपःरीत पूंजी के मुक्त प्रवाह की अनुमतः नहीं दे सकती है ।
  - एक नश्चितः वनःमिय दर व्यवस्था में घरेलू मुद्रा अन्य वदःशी मुद्राओं जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लःगः आदः की एक बास्केट से जुड़ी होती है ।
- एक सक्षम नीतः निर्माता, कःसी भी समय, इन तीन उद्देश्यः में से दो को प्राप्त कर सकता है ।
- यह वचःार 1960 के दशक की शुरुआत में कनाडा के अर्थशास्त्री रॉबर्ट मुंडेल और ब्रिटःशः अर्थशास्त्री मारकस फ्लेमःगः द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रस्तावतः कःया गया था ।
- इम्पॉसबिल ट्रनिटी अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र और मौद्रकः नीतः में एक मौलकः अवधारणा है ।
- यह उन अंतरनहितः चुनौतयः का वर्णन करती है जनःका सामना देश अपनी वनःमिय दर और पूंजी प्रवाह से संबंधतः तीन वशिष्टः नीतःगत उद्देश्यः को एक साथ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ।

#### चुनौतयः:

- जब कोई देश मुक्त पूंजी प्रवाह और नश्चितः वनःमिय दर को प्राथमकःता देता है, तो वह अपनी मौद्रकः नीतः पर नश्चितःरण खो देता है, जसःसे वह बाह्य आर्थकः दबावों के प्रति संवेदनशील हो जाता है ।
- यदः कोई देश एक नश्चितः वनःमिय दर और स्वतंत्र मौद्रकः नीतः बनाए रखना चाहता है, तो उसे अपनी सीमाओं के वपःरीत धन के प्रवाह को सीमतः करने के लयः पूंजी नश्चितःरण लागू करना होगा ।
- स्वतंत्र मौद्रकः नीतः और मुक्त पूंजी प्रवाह का वकःल्प चुनने के लयः वनःमिय दर में उतार-चढ़ाव को स्वीकार करने की आवश्यकःता होती है, जसःसे संभावतः रूप से अस्थःरःता उत्पन्न हो सकती है ।

#### इम्पॉसबिल ट्रनिटी के उदाहरणः

- वभिन्न देशों ने इम्पॉसबिल ट्रनिटी की चुनौतयः का सामना कःया है, जनःमें से कुछ उल्लेखनीय उदाहरण वर्ष 1997 में एशयःई वत्तःतीय संकट और वर्ष 1992 में यूरोपीय वनःमिय दर तंत्र संकट हैं ।
  - इन संकटों को आंशकः रूप से प्रभावतः देशों की नश्चितः वनःमिय दरों, स्वतंत्र मौद्रकः नीतयः और मुक्त पूंजी प्रवाह को एक साथ बनाए रखने में असमर्थता हेतु ज़मःमेदार ठहराया गया था ।

### भारत का इम्पॉसबिल ट्रनिटी से जूझना:

- इम्पॉसबिल ट्रनिटी को संबोधतः करने के लयः रणनीतयः और कार्यः
  - ब्याज दरों का प्रबंधनः

- अमेरिकी फेडरल रज़िर्व की तुलना में RBI ब्याज़ दरें बढ़ाने में सतर्क रहा है।
  - दरें बढ़ाने की अनिच्छा मंदी उत्पन्न होने के भय से प्रेरित है, खासकर वर्ष 2024 में आगामी चुनावों के साथ।
- कम ब्याज़ दर मध्यस्थता अमेरिका (वशिव की आकर्षण मुद्रा) में पूंजी की उड़ान और भारतीय रुपए के आसन्न मूल्यह्रास का संकेत देती है।
- **वदेशी मुद्रा भंडार की संरचना:**
  - भारत के **वदेशी मुद्रा भंडार** में मुख्य रूप से 'हॉट मनी' (वदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) से जो मध्यस्थता के अवसरों का लाभ उठाने के लिये घरेलू ऋण या इक्विटी बाज़ारों में निवेश करते हैं) और कॉर्पोरेट उधार (उदाहरण के लिये, अडानी ग्रीन एनर्जी, वेदांता, आदि) शामिल हैं, ना कव्यापार से कमाया गया धन।
    - व्यापार के माध्यम से अर्जति नहीं किये गए भंडार पर विश्वास करना मुद्रा स्थिरता बनाए रखने के लिये चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
  - **पूंजी नियंत्रण लागू करना:**
    - भारत ने पूंजी प्रवाह को नियंत्रित करने के लिये विभिन्न उपाय लागू किये हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता अभी अनिश्चित बनी हुई है।
    - पूंजी बहर्प्रवाह को नियंत्रित करने के नीतित उपाय:
      - **आयात प्रतिबंध और लाइसेंसिंग नीतियाँ:**
        - भारत ने पूंजी के बहर्प्रवाह को सीमित करने की त्वरित प्रतिक्रिया के रूप में, विशेष रूप से **इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध** लगाया।
        - इन प्रतिबंधों को बाद में घरेलू वनिरिमाण सीमाओं के कारण **लाइसेंस-आधारित आयात नीतियों** में बदल दिया गया।
        - हालाँकि, ये उपाय अनजाने में पूंजी के बहर्प्रवाह को रोकने के बजाय आपूर्ति-तन्त्र मुद्रास्फीति में योगदान कर सकते हैं।
      - **कर दरों में परिवर्तन:**
        - भारत ने पूंजी के बहर्प्रवाह को प्रतिबंधित करने के साधन के रूप में आउटबाउंड प्रेषण पर कर दरों को 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया है।
        - **'इम्पॉसबिल ट्रनिटी'** के प्रबंधन में इस कर वृद्धि की प्रभावशीलता जाँच के दायरे में है।
  - **भारत की आर्थिक स्थिति पर चीन का प्रभाव:**
    - **चीन की अपस्फीति** और विभिन्न दरों में कटौती का उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। चीनी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई में पिछले वर्ष की तुलना में 0.3% गिर गया। इसके अतिरिक्त, चीनी युआन के मुकाबले INR में 4% की वृद्धि हुई है।
    - भारतीय रुपए के मज़बूत होने के परिणामस्वरूप चीन से आयात में वृद्धि हो सकती है जो अंततः भारत के व्यापार संतुलन तथा मुद्रा गतिशीलता प्रभावित कर सकती है।
    - चीनी मुद्रा युआन के मूल्यह्रास से वैश्विक बाज़ारों में भारत का निर्यात कम प्रतिस्पर्धी हो सकता है।
  - **वदेशी संस्थागत निवेशक (Foreign Institutional Investors- FIIs) और भारतीय ऋण:**
    - वदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय ऋण प्रतिभूतियों की हसिसेदारी बेचे जाने तथा वदेशों में अधिक लाभदायक निवेश की तलाश करने से वदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि देखी जा रही है और वदेशी मुद्रा बाज़ार में भारतीय रुपया कमज़ोर हो रहा है।

## भारतीय निवेशकों के लिये इम्पॉसबिल ट्रनिटी के नहितार्थ:

- रुपए के मूल्यह्रास से सुरक्षा:
  - सूचना प्रौद्योगिकी और फार्मा जैसे क्षेत्रों में निवेश, जिनमें कमाई मुख्य रूप से डॉलर में होती है, रुपए के मूल्य में गिरावट कम कर सकते हैं।
  - रुपया कमज़ोर होने के समय इन कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता में संभावित वृद्धि लाभकारी रटिर्न दे सकती है।
- वदेशी में निवेश में विधिता लाना:
  - निवेशकों को 'इम्पॉसबिल ट्रनिटी' द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को स्वीकार करने के लिये स्वयं को अनुकूलित करना चाहिये।
  - चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थिति में, पूंजी की सुरक्षा के लिये अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्तियों में निवेश करना आवश्यक हो जाता है।

## आगे की राह

- भारत को पूंजी नियंत्रण उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर ध्यान देना चाहिये। इन उपायों से मुद्रा स्थिरता बनाए रखने और वदेशी निवेश को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।
- देश को सक्रिय रूप से अपने वदेशी मुद्रा भंडार में विधिता लाना चाहिये और वदेशी निवेशकों के 'हॉट मनी' पर बहुत अधिक निर्भर रहने के बजाय व्यापार के माध्यम से लाभ अर्जति करने का लक्ष्य रखना चाहिये।
- इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष वदेशी निवेश को आकर्षित करने से मुद्रा स्थिरता में मदद मिल सकती है और रुपया मज़बूत हो सकता है।
- भारतीय रज़िर्व बैंक को मुद्रास्फीति नियंत्रण और वदेशी निवेश को आकर्षित करने संबंधी कार्यों पर विचार करते हुए ब्याज़ दरों के संदर्भ में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। ब्याज़ दर का क्रमिक समायोजन इस संतुलन को हासिल करने में मदद कर सकता है।

